and fish processing industry. This year's Budget has increased its allocation in this regard from Rs. 325/- crores to Rs. 461/- crores. But, still, this is a very small amount considering that fisheries is the third largest livelihood generator after agriculture and weaving in this country. On behalf of the DMK, I urge the Prime Minister and the Government to take this up immediately and set up a Ministry for Fisheries which can address the problems of the Indian fishermen, their security and put an end to their troubles.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (Nominated): Sir, I associate myself with the point raised by the hon. Member.

SHRI P. RAJEEVE (Kerala): Sir, I also associate myself with the point made by the hon. Member.

SHRI C.P. NARAYANAN (Kerala): Sir, I too associate myself with the point raised by the hon. Member.

Atrocities against dalits at tigaon village in Faridabad, Haryana

श्री रामदास अठावले (महाराष्ट्र) : उपसभापति जी, भारत में जो दलित हैं, उनके ऊपर गाँव-गाँव में बहुत अत्याचार हो रहे हैं। महात्मा गाँधी जी ने सभी दलितों को न्याय देने की बात कही थी, लेकिन गाँवों में आज भी अनटचेबिलिटी है। यदि कोई दलित पढ़ाई करता है और किसी सवर्ण समाज की लड़की के साथ प्यार करता है एवं शादी करना चाहता है, तो उसका मर्डर हो जाता है। महाराष्ट्र में खरड़ा नाम का एक गाँव है, वहाँ पर सत्रह साल के एक नौजवान की हत्या कर दी गई। दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद जिले में तिगाऊँ नाम का गाँव है। वहाँ पर जगदीश नाम का लड़का एक राशनिंग डिपो चलाता है। गुर्जर समाज के दो-तीन आदमी उसके पास गए और कहा कि हमें राशन कार्ड चाहिए, इसके लिए इन ब्लैंक फॉर्म्स पर सिग्नेचर करो। वह बोला कि आप पहले फॉर्म्स भर लीजिए, मैं बाद में सिग्नेचर कर दूंगा। उन्होंने कहा कि तू दलित है, हमारा गुलाम है और हमारे साथ ऐसे बात करता है? उन्होंने उसको मारा। उसके बाद 26 जून को, गुर्जर समाज के लगभग 250 लोग उस बस्ती में आए और 50 गाड़ियाँ तोड़ दीं। अभी वहाँ पर 8 लोग जख्मी हैं। दिल्ली के नजदीक यह सब हो रहा है। पूरे देश में, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, कई राज्यों में ऐसा हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब लोक सभा और राज्य सभा में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, 1989 पास हुआ था, तो 20 घंटे तक चर्चा हुई थी। सभी मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट और सभी पार्टियों ने यह स्वीकार किया था कि दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। आज हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन इस अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यह केवल सरकार का काम नहीं है, यह हम सब लोगों का काम है। समाज को जोड़ने का जो काम है, जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा है, उसमें सोशल, इकोनॉमिक इक्वेलिटि प्रस्तावित करने की बात है, लेकिन संविधान एक बाजू में है, हमारा कानून एक बाजू में है और दूसरी ओर हम एक-दूसरे पर अत्याचार कर रहे हैं। मैंने तो बहुत बार मांग की है कि दलितों और सवर्णों को इकट्ठा लाना चाहिए। जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने आरपीआई की स्थापना की थी, तो उसके पीछे उनकी भावना इतनी थी कि दलितों और सवर्णों को एक करना चाहिए, जातिवाद को खत्म करना चाहिए और अपने देश में समानता स्थापित होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हम सवर्णों के खिलाफ नहीं हैं। सर, मैंने सवर्ण समाज के लोगों, उच्च वर्गीय समाज के लोगों के लिए

[श्री रामदास अठावले]

लोक सभा में माँग कि थी कि दलित, आदिवासी और ओबीसी को जिस तरह आरक्षण मिलता है, उसी तरह ब्राह्मण, मराठा, राजपूत, क्रिश्चियन, लिंगायत आदि समाज में जो इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनको भी मंडल कमीशन के मुताबिक आरक्षण मिलना चाहिए। हमें इस झगड़े को खत्म करना चाहिए। गुर्जर को भी आरक्षण मिलना चाहिए, जाट को भी मिलना चाहिए, मराठा को भी मिलना चाहिए। मेरा कहना यह है कि मेरा विषय एट्रोसिटीज़ का है। ...(**समय की घंटी**)....

श्री उपसभापति : आपका समय समाप्त हो गया। ...(**व्यवधान**)... ओके, आपका टाइम ओवर हो गया। त्यागी जी, आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)... अठावले जी आप, बैठिए। आपका टाइम खत्म हो गया। त्यागी जी, आप बोलिए।

Recent Attack on Palestine by Israeli Army

श्री के. सी. त्यागी (बिहार) : सर, पिछले एक सप्ताह में लगातार निर्दोष फिलिस्तिनियों पर अत्याचार हो रहे हैं। यह बहुत पुरानी समस्या है, अगर मैं उसके विस्तार में जाऊँगा, तो आप समय भी नहीं देंगे। उनकी तीन पीढ़ियां तम्बुओं में पैदा हुई हैं। अमेरिका इजरायल को इकोनॉमिकली और मिलिट्रीवाइज़ सपोर्ट करने के लिए 8 मिलियन डॉलर पर डे खर्च करता है। भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और नासिर साहब ने मिल कर गुटनिरपेक्ष देशों की कल्पना की थी और उसे अस्तित्व में लाए थे, जिसे बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी और यासर अराफात ने मिल कर पश्चिम एशिया से लेकर पूरी दुनिया में फैलाया था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधान मंत्रित्व काल में भी कई मौकों पर उन्होंने फिलिस्तिनियों की मदद की थी। यह पहला अवसर है, बाजारवाद का असर है और अमेरिकी* का असर है कि दुनिया का कोई भी मुल्क उन निहत्थे लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। मेरे पास समाचार पत्र की एक कटिंग है, जिसमें से मैं एक लाइन पढ़ कर सुनाने की इजाजत चाहता हूं। इसमें लिखा है, 'The mother of a four year old Palestinian girl killed in an Israeli air attack.' एक चार साल की बच्ची रमज़ान के मुकद्दस महीने में, जिसको अगली ईद का इंतजार था, जिसके माँ-बाप उसकी बहबूदी के लिए दुआएँ करते, वह चार साल की बच्ची भी इजरायल के अटैक में मरी है। इस पर पूरी दुनिया खामोश है। भारत ऐसी तमाम तहजीबों का और इस तरह की तमाम चीजों का समर्थन करता रहा है। यह हमारा सिद्धांत रहा है कि हम तमाम ब्रह्मांड के लोगों का ध्यान रखते हैं। अच्छा होता है कि हमारी काबिल विदेश मंत्री यहाँ होतीं, लेकिन मुझे अफसोस है कि विदेश मंत्री ने भी अब तक इस विषय में कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की है। मून साहब, जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका कल का रिज़ोलुशन मेरे पास है। शायद आज सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी हो सकती है, जिसमें यह प्रस्ताव आए, लेकिन मुझे यह अफसोस है कि क्या कारण है कि भारत सरकार ने अब तक इस पर रिएक्ट नहीं किया। यह बात मैं अपनी बाईं बाजू के मित्रों के लिए इलज़ाम के तौर पर नहीं कहना चाहता, न ही मैं सारी पार्टी के लिए यह कह रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, जिनकी इज़राइल के साथ भी हमदर्दी रहती है। मैं चाहता हूं कि कम-से-कम इस सदन में इस तरह का प्रस्ताव पास होना चाहिए कि इस समय फिलिस्तीन और इज़रायल के लोगों में जो झगड़ा चल रहा है,....(**समय की घंटी**)... उसको समाप्त करने के लिए और 7 लाख के करीब जो रिफ्यूजी हैं, जो पिछली तीन पीढ़ियों से टेंटों में

*Expunged as ordered by the Chair.